मदन लाल और अन्य

बनाम

बाल कृष्ण और अन्य

14 नवंबर, 2005

[अरिजीत पासायत और तरुण चटर्जी, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 100-दूसरी अपील-उच्च न्यायालय द्वारा कानून-न्याय के पर्याप्त प्रश्न को तैयार किए बिना निपटानःउच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करे और तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई करे-इसके अभाव में, इस तरह के निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है-कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के बाद मामले को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

इस अपील में, यह मुद्दा शामिल था कि क्या उच्च न्यायालय धारा 100 सी.पी.सी. द्वारा अनिर्वाय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना दूसरी अपील को स्वीकार करने में उचित था।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. धारा 100 सी.पी.सी., 1908 को ध्यान में रखते हुए, अपील के ज्ञापन में धारा 100 की उप-धारा (3) के तहत आवश्यक अपील में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्नों या कानून के प्रश्नों को सटीक रूप से बताया जाएगा। जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को उप-धारा (4) के तहत तैयार करेगा और दूसरी अपील की सुनवाई इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी जैसा कि धारा 100 सी.पी.सी. की उप-धारा (5) में कहा गया है। [737-एफ, जी]

1.2. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है या दूसरी अपील की सुनवाई इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न, यदि कोई हो, पर की गई थी और इस तरह के निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है। कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कोई हो, तैयार करने के

बाद और कानून के अनुसार मामलों को निपटान के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है। [738-ई; 739-एफ]

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, [2000] 1 एस.सी.सी. 434; रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000] 3 एस.सी.सी. 708; कन्हैयालाल और अन्य बनाम अनुपकुमार और अन्य, जे.टी. (2002) 10 एस.सी. 98; प्रेमबाई बनाम जनेश्वर रामकृष्ण पतंगे और अन्य, (2003) ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 2922; चडत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य। जे.टी. [2004] 6 एस.सी.सी. 296 और मथकला कृष्णैया बनाम वी. राजगोपाल, जे.टी. [2004] 9 एस.सी.सी. 205 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :

सिविल अपील सं. 918/2000

1992 के आर.एस.ए. सं. 273 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 2.8.98 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थीयों के लिए गोपाल बलवंत साठे।

उत्तरदाताओं के लिए रमेश बाबू एम.आर

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अरिजीत पासायत, जे.

इस अपील में चुनौती सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के तहत वरीयता प्राप्त दूसरी अपील में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए है। विवादित निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को दरकिनार कर दिया और वादी के मुकदमे को मालिकाना हक और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए घोषित कर दिया, जैसा कि अनुरोध किया गया था। हालाँकि अपील के समर्थन में कई बिंदुओं का आग्रह किया गया था, लेकिन मूल रूप से यह तर्क दिया गया था कि दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को कानून के प्रश्न को तैयार किए बिना भी दरकिनार कर दिया गया था।

दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि विशेष रूप से कानून के प्रश्नों को तैयार नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर लागू कानूनी स्थिति पर सही ध्यान दिया है और अपील की अनुमति दी है।

संहिता की धारा 100 को ध्यान में रखते हुए अपील के ज्ञापन में धारा 100 की उप-धारा (3) के तहत आवश्यक रूप से अपील में शामिल पर्याप्त प्रश्न या कानून के प्रश्नों का सटीक उल्लेख किया जाएगा। जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को उप-धारा (4) के तहत तैयार करेगा और दूसरी अपील की सुनवाई धारा 100 की उप-धारा (5) में बताए गए इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न पर की जानी है।

संहिता की धारा 100 "दूसरी अपील" से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार हैः

"धारा 100-

(1) अन्यथा निकाय में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़ दें। इस संहिता या तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

(2) इस धारा के तहत एकतरफा पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।

(3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात, न्यायालय द्वारा प्रणीत नहीं किए गए विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले ऐसा प्रश्न शामिल है।"

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है या इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न, यदि कोई हो, पर दूसरी अपील की सुनवाई की गई थी। ऐसा होने पर, निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, [2000] 1 एस.सी.सी. 434) में इस न्यायालय ने पैरा 10 में इस प्रकार कहा हैः

> "10. अब सी.पी.सी. की धारा 100 के तहत, 1976 के संशोधन के बाद, उच्च न्यायालय के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना आवश्यक है और ऐसा किए बिना पहले अपीलीय न्यायालय के फैसले को उलटने की अनुमति नहीं है।"

फिर भी रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000] 3 एस.सी.सी. 708 में इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ी अपीलों तक ही सीमित है। उक्त निर्णय के पैरा 7 में कहा गया हैः

"7. यह दोहराया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय की धारा 100 सी.पी.सी. के अधिकार क्षेत्र के तहत दूसरी अपील पर विचार करना केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह नहीं है उच्च न्यायालय को धारा 100 सी. पी. सी. के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्य के शुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। इसके अलावा, मामले का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील स्वीकार करते समय उसके द्वारा तैयार किए गए कानून के प्रश्न पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि विवादित फैसले में इसका कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, तथ्य निष्कर्ष अदालतों ने साक्ष्य की सराहना करने के बाद कहा कि प्रतिवादी ने एक बटाई के रूप में परिसर के कब्जे में प्रवेश किया, अर्थात, एक किरायेदार के रूप में और उसका कब्जा अनुमत था और इस बारे में कोई अभिवचन या सबूत नहीं था कि यह कब प्रतिकूल और शत्रुतापूर्ण हो गया। नीचे दी गई दोनों

अदालतों द्वारा दर्ज किए गए ये निष्कर्ष साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित थे और उन निष्कर्षों में कोई विकृति, अवैधता या अनियमितता नहीं थी। यदि प्रतिवादी को पट्टेदार के रूप में या बटाई समझौते के तहत वाद भूमि का कब्जा मिल गया है, तो अनुमेय कब्जे से उसे वास्तविक मालिक के ज्ञान के प्रतिकूल शत्रुतापूर्ण शत्रुता और कब्जे को दिखाने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित करना है। लंबे समय तक केवल कब्जे के परिणामस्वरूप अनुमत कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित नहीं किया जाता है (ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार, [1994] 6 एससीसी 591)। इसलिए उच्च न्यायालय को दोनों नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।"

इस स्थिति को कन्हैयालाल और अन्य बनाम अनुपकुमार और अन्य, जे.टी. (2002) 10 एस.सी. 98, में दोहराया गया है।

प्रेमाबाई बनाम जनेश्वर रामकृष्ण पटांगे और अन्य, (2003) ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 2922, चडत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य, जे.टी. [2004] 6 एस.सी.सी. 296 और मथकला कृष्णैया बनाम वी. राजगोपाल, जे.टी. [2004] 9 एस.सी.सी.205।

इन परिस्थितियों में, विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। हम मामले को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कोई हो, और कानून के अनुसार तैयार करने के बाद निपटान के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं। अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

एन.जे.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।